

भारतीय कानून में लैंगिक पूर्वाग्रह

प्रलिस के लयः

[जनहति याचिका, सर्वोच्च नयायालय, दहेज नषध अधनियम, 1961, धारा 498A, भारतीय दंड संहति, दंड प्रकरया संहति, 1973, घरेलू हसिा से महलियाँ का संरक्षण अधनियम, 2005, वधिआयोग।](#)

मेन्स के लयः

दहेज और घरेलू हसिा कानूनों का दुरुपयोग और संबधति मुद्दे, लगी तटस्थ कानून की आवश्यकता

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में, बंगलूरु में एक तकनीकी वशिषज्ञ के आत्महत्या करने के बाद [सर्वोच्च नयायालय](#) में एक [जनहति याचिका \(PIL\)](#) दायर की गई है, जसिमें [दहेज और घरेलू हसिा से जुड़े मौजूदा कानूनों](#) की समीक्षा और सुधार का अनुरोध कया गया है ताक उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

- याचिका में कहा गया है क [दहेज नषध अधनियम, 1961](#) और [भारतीय दंड संहति \(अब भारतीय नयाय संहति\)](#) की [धारा 498A](#) का दुरुपयोग असंबधति वविादों को नपिटाने और पत्निके परिवार को परेशान करने के लयि कया गया है।

भारतीय कानून कसि प्रकार लगी-पक्षपाती है?

- IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु):** समय के साथ लोगों को यह वशिवास दलियाया गया क वविाहति भारतीय महिला की हर अप्राकृतिक या असामयिक रूप से हुई मृत्यु दहेज मृत्यु है।
 - ऐसे मामलों में पत्निका रशितेदार को कम-से-कम सात वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाएगी, जसिे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- IPC की धारा 498A (महलियाँ के प्रतिकूरता):** धारा 498A के तहत वविाहति महिला के प्रतिकूरता या उत्पीडन का दोषी पाए जाने पर पत्निका उसके रशितेदारों को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
 - धारा 304B एक गैर-ज़मानती, गैर-समझौता योग्य और संज्जेय अपराध है, जसिका अर्थ है कयिद आरोप झूठा भी हो तब भी मुकदमा चलेगा और पत्निको नरिदोष साबति होने तक दोषी माना जाएगा।
 - राष्ट्रीय अपराध रकिर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 में लगभग 200,000 लोगों को अप्रमाणति दहेज के आरोपों में गरिफ्तार कया गया, जनिमें से केवल 15% अभयिकृतों को दोषी ठहराया गया।
- IPC की धारा 375 (बलात्कार):** IPC की धारा 375 के तहत केवल पुरुष ही अपराधी हो सकते हैं और महलियाँ ही बलात्कार की शकिार हो सकती हैं। यह धारा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को बलात्कार पीडति के रूप में मान्यता नहीं देती है।
 - भारतीय दंड संहति की धारा 377 पुरुष पीडतियों के लयि एकमात्र वकिल्प है, लेकनि इसमें कई चुनौतयिाँ हैं तथा यह्युरुषों द्वारा पुरुषों पर कयिे जाने वाले यौन शोषण को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।
- BNS की धारा 69:** यह "धोखे से यौन संबध बनाने" को अपराध मानती है, जसिमें "बनिा इरादे के कसिी महिला से शादी करने का वादा करना" भी शामिल है, जसिके लयि 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
 - शादी के वादे पर सहमति से बनाया गया यौन संबध तभी अपराध माना जाएगा जब पुरुष इससे मुकर जाए, महिला नहीं।
 - "शादी का वादा" करना गैरकानूनी है, जसिसे कसिी वयकृतीकी नजिता और स्वायत्तता के अधकिार का उल्लंघन हो सकता है, जबक इस तथय की अनदेखी की जा सकती है क महिला ने स्वेच्छा से इस रशिते में प्रवेश कया है।
- IPC की धारा 354:** यह महिला की मर्यादा और मान सम्मान को कषति पहुँचाने के लयि उस पर कया गया हमला या उसके साथ गलत मंशा के साथ ज़ोर जबरदस्ती है। हालाँक पुरुष और ट्रांसजेंडर की मर्यादा और मान सम्मान की रक्षा के लयि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।
 - ऐसे मामले भी देखने को मलिते हैं जनिमें महलियाँ पुरुषों को धमकाती हैं तथा इसके लयि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता (कयोंक देश के कानून में ऐसे अपराधों से पुरुषों की रक्षा नहीं की गई है) है।
- CrPC अधनियम, 1973 की धारा 125:** भारत में दंड प्रकरया संहति, 1973 की धारा 125 के तहत न केवल पत्नी बल्क उसके माता-पति

प्रश्न 3. महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मलिनल चाहलल । टपलणल कीऑल । (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gender-bias-in-indian-law>

